

समक्ष माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

पूरनलाल नाई तनय बैनीप्रसाद नाई
निवासी ग्राम पीरा, तह. राजनगर छतरपुर (मोप्र)

टीम-५४६-॥१६

.....आवेदक

मोप्र० शासन

// विरुद्ध //

....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा-50 म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त आवेदक ने न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर जिला छतरपुर (म.प्र.) के प्रकरण क्रमांक 66 / अप्रैल / अ-89-अ / अ-13 / 2014-15 में पारित आदेश दिनांक 04-01-2016 में पारित आदेश के विरुद्ध परिवेदित होकर यह निगरानी निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता है:-

1. यह कि, प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अनुविभागीय अधिकारी राजनगर के समक्ष म.प्र.भू.रा.सं. की धारा 44 में प्रस्तुत अप्रैल का निराकरण 30.07.11 को किए जाने पर माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका क्र. 150614 / 2015 आदेश दिनांक 11.08.15 के निर्देशानुसार प्रकरण न्यायालय कलेक्टर छतरपुर के समक्ष प्रस्तुत किया था जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी सूक्ष्म जांच एवं दस्तावेजी साक्ष्य का परिक्षण किए बिना आवेदकगणों द्वारा प्रस्तुत अप्रैल निरस्त किए जाने से यह निगरानी विधिवत रूप से श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।
2. यह कि, आलोच्य आदेश प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य एवं व्याप्त कानूनी सिद्धांतों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्ट्या ही निरस्त किए जाने हैं।
3. यह कि, आवेदक अपने अन्य भाईयों के साथ लगभग 15 वर्ष पूर्व किए गए वटवारे अनुसार काबिज चला आ रहा है। विवादित भूमि उसकी पुस्तैनी भूमि है तथा पुस्तैनी कार्य नाई का होने के कारण परिवार के अन्य भाईयों द्वारा अपनी आर्थिक स्थिति सुधार करने एवं पारिवारिक कर्ज चुकाने के कारण कुछ कृषि भूमि का विक्रय कई वर्ष पूर्व किया था जिसका आधार लेते हुए प्रश्नगत आदेश के तहत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा संपूर्ण भूमि के साथ-साथ आवेदक के कब्जे वाली भूमि को भी अवैद्य कॉलोनी की श्रेणी में मान्य करते हुए प्रवंधन शासन पक्ष एवं प्रतिबंधित किए जाने का विवादित आदेश पारित किया है जिसकी पुष्टि कलेक्टर छतरपुर द्वारा किए जाने से पारित दोनों आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं हैं।

Bse

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

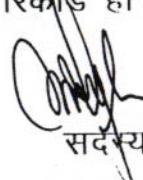
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R-546/।।।।। 16.....जिला छतरपुर.....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-2-16	<p>1— आवेदक की ओर विद्वान अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव उपस्थित अनावेदक शासन पक्ष की ओर से पेनल अधिवक्ता उपस्थित दोनों पक्षों के तर्क श्रवण किए गए।</p> <p>2— मैंने प्रकरण का आवलोकन किया। यह निगरानी न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर जिला छतरपुर (म.प्र.) के प्रकरण क्रमांक 66/अप्रैल/अ-89-अ/अ-13/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 04-01-2016 के विरुद्ध भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-50 के तहत प्रस्तुत की गयी है।</p> <p>3— आवेदक द्वारा तर्क में कहा गया है कि आवेदक अपने अन्य भाईयों के साथ लगभग 15 वर्ष पूर्व किए गए बटवारे अनुसार काबिज चला आ रहा है। विवादित भूमि ख.नं. 1517/2/2/क/1 का रकवा कमशः 1.393 एवं 1.392 भूमि आवेदक एवं उसके भाईयों की पुस्तैनी भूमि है तथा पुस्तैनी कार्य नाई का होने के कारण परिवार के अन्य भाईयों द्वारा अपनी आर्थिक स्थिति सुधार करने एवं पारिवारिक कर्ज चुकाने के कारण कुछ कृषि भूमि का विक्रय कई वर्ष पूर्व किया था जिसका आधार लेते हुए अनुविभागीय अधिकारी द्वारा संपूर्ण भूमि के साथ-साथ आवेदक के कब्जे वाली भूमि को भी अवैद्य कॉलोनी की श्रेणी में मान्य करते हुए प्रबंधन शासन पक्ष एवं प्रतिबंधित किए जाने का आदेश पारित किया है जिसके विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश उपरांत भी प्रस्तुत अपील की पुष्टि कलेक्टर छतरपुर द्वारा किए जाने से पारित आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया है।</p> <p>4— आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया है कि अनुविभागीय अधिकारी राजनगर द्वारा उपपंजीयक कार्यालय राजनगर से भूमि के विक्रय की जानकारी प्राप्त की है जिसमें उनके दिए गए प्रतिवेदन अनुसार आवेदक द्वारा किसी भी भूमि का विक्रय नहीं किए जाने के उपरांत भी आवेदक के कब्जे वाली भूमि को भी सम्मिलित कर प्रबंधन शासनपक्ष एवं प्रतिबंधित किए जाने की कार्यवाही की गई है जबकि आवेदक गण बटवारा अनुसार अपनी भूमि पर काबिज चला आ रहा है</p>	

R 0546-4/16(छत्रपति)

(2)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
	<p>इस कारण आवेदक की कब्जे वाली भूमि को प्रतिबंधन से मुक्त करते हुए पारित आदेश को निरस्त किए जाने का आग्रह किया गया है।</p> <p>5— अनावेदक शासन की ओर से अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया है कि कलेक्टर जिला छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.01.2016 में कोई वैद्यानिक त्रुटि नहीं किए जाने से पारित आदेश को स्थिर रखते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया है।</p> <p>6— उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया अनुविभागीय अधिकारी द्वारा हल्का पटवारी के प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नाधीन भूमि डायर्वर्सन के बिना भूमि का विक्रय किए जाने के कारण अवैद्य कालोनी का निर्माण करने पर आवेदक के साथ गोविन्ददास, नवल किशोर एवं रामकिशोर के विरुद्ध आदेश पारित किया है प्रश्नाधीन भूमि 1/4 भाग पर सभी पक्षों का रजिस्टर्ड वटवारा हुआ है। उपपंजीयक कार्यालय राजनगर के दिए गए प्रतिवेदन अनुसार क्रमांक 1, 2, व 3 में गोविन्ददास नवलकिशोर, रामकिशोर पुत्र बैनीप्रसाद द्वारा एवं क 4 में पियुष पुत्र प्रयाग नारायण द्वारा विवादित कृषि भूमि का विक्रय किये जाने का उल्लेख है आवेदक पूरनलाल द्वारा भूमि का विक्रय किया जाना नहीं पाया जाता। अतएव प्रस्तुत तर्कों एवं उपपंजीयक राजनगर के प्रतिवेदन के आधार पर प्रश्नगत आदेश हस्तक्षेप योग्य पाता हूँ।</p> <p>7— उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.01.16 एवं अनुविभागीय अधिकारी राजनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.07.11 में आवेदक पूरननाई को रजिस्टर्ड वटवारा अनुसार 1/4 हिस्से की भूमि रकवा 0.677 को शासनहित एवं प्रतिबंधन से मुक्त करते हुए आवेदक के नाम यथावत रखे जाने के निर्देश दिए जाते हैं शेष भूमि के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी एवं कलेक्टर छतरपुर द्वारा पारित आदेश यथावत रखा जाता है तदानुसार यह निगरानी इसी स्तर पर निराकृत की जाती है प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p> <p style="text-align: right;"> सचिन सिंह</p> <p style="text-align: left;">१५८८</p>	